

प्रेषक,

पी०क०महान्ति,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड।

लघु सिंचाई विभाग

देहरादून : दिनांक 06 दिसम्बर, 2007

विषय : वित्तीय वर्ष 2007 - 08 के लिए जिला योजना के अन्तर्गत आयोजनागत भद्रों में घनायंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि लघु सिंचाई विभाग के लिए वर्ष 2007-08 में जिला योजना के अन्तर्गत प्राविधिक बजट की घनराशि में से ₹0 197.40 लाख (रूपये एक करोड़ सत्तानवे लाख चालीस हजार रुपये) जिसका विवरण संलग्नक में अंकित है, को लघु सिंचाई विभाग से सम्बन्धित सिंचाई योजनाओं के वित्तान्वयन हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- 1- अवमुक्त की जा रही घनराशि का उपर्योग शासनादेश सं0 1454 / 11-2007 -14(05) / 2005 दिनांक 06.12.2007 में निहित प्राविधानानुसार किया जायेगा।
- 2- सम्बन्धित घनराशि का व्यय केवल घालू कार्यों के विलक्ष ही किया जाय, व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है। घनराशि के अन्यत्र विवरण की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यवितरण रूप से उत्तरदायी होंगे। जिला योजना से सम्बन्धित कार्यों पर व्यय जिला अनुबंध समिति द्वारा स्वीकृत परिव्यय एवं इसके अन्तर्गत अनुमोदित योजनाओं के अनुसार ही किया जाय।
- 3- घनराशि व्यय करने से पूर्व रक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृत एवं कार्यों के प्राककलन रक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।
- 4- उक्त व्यय में बजट मैनुअल, दितीय हस्तपुस्तिका, टैण्डर, कुटेशन विषयक नियम तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में रामब-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।
- 5- स्वीकृत घनराशि का खण्डवार विभाजन/फॉट सम्बन्धित अधिकारी द्वारा किया जायेगा, जिसका विवरण शासन को भी उपलब्ध कराया जायेगा। जिला योजना की फॉट जिला अनुश्रवण समिति द्वारा स्वीकृत परिव्यय के आधार पर की जाय।
- 6- जहाँ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यों के सम्बन्ध में धर्थीचित भूकार्प निरोधी तकनीकी का ग्रयोग किया जाय।

(2)

- 7— स्थीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रभान्— पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक नहालेखाकार उत्तराखण्ड एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।
- 8— कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 9— विभागीय कार्य करने से पूर्व लघु सिंचाई विभाग/लोक निर्माण विभाग की दरों पर आगणन गठित कर एवं तकनीकी अधिकारियों की संस्तुति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- 10— व्रेमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्थीकृत की जा रही धनराशि का मार्च 2008 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

इस सम्बन्ध में होने याला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के आद्य-व्यायक की अनुदान स-०-२० के अन्तर्गत संसम्बन्ध में उल्लिखित उपलेख शीर्षकों के अन्तर्गत सुसंगत प्राचार्यमिक इकाईयों के नामे दाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या—342(P)/XXVII-4 /2007 दिनांक 06.11.2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न : यथोक्त।

भवदीय,

(पी० के० महन्ति)
सचिव

संख्या— 1455 / ।।—2007—03(13) / 05, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को रावनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1— महालेखाकार, ओबराय मौटर्स विलिंग, राहारनपुर रोड, देहरादून।
- 2— वित्त वित्त अनुभाग—४
- 3— श्री एम०एल० पन्त, अपर सचिव, वित्त, बजट, अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4— नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 5— निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री।
- 6— अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 7— सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
- 8— निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 9— गार्ड फाईल।

संलग्न : यथोक्त।

१८
(एस० एस० टोलिया)
अनु सचिव

शासनादेश सं०-१४५५ / ।।-२००७-०३ (१३) / ०५, विनांक ०६ दिसम्बर, २००७ का संलग्नक।

(रूपये एक करोड़ सत्तानवे लाख चालीस हजार मात्र)

(एस०एस० टोलिया)
अग्र सचिव।